

हदी भाषा ववाद

प्रलिमिंस के लयि:

हदी, भाषा आयोग, राजभाषा अधनियिम 1963 के प्रचार से संबंघति संवैधानकि प्ररावधान ।

मेन्स के लयि:

आधकिरकि/राष्टरीय भाषा के रूप में हदी का उपयोग, त्रभाषा सूत्र, हदी वरीधी आंदोलन आदी।

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई राजभाषा समति की रिपोर्ट के 11वें खंड पर कुछ दक्षिणी राज्यों की नाराज़गी की प्रतिकरियाएँ सामने आई हैं (वे रिपोर्ट को उन पर हदी थोपने के प्रयास के रूप में देखते हैं) ।

पैनल की सफिरशैं:

- हदी भाषी राज्यों में IIT, IIM और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शकिषा का माध्यम हदी होना चाहयि ।
- प्रशासन में संचार के लयि इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हदी होनी चाहयि और पाठ्यक्रम को हदी में पढ़ाने का प्रयास कयि जाना चाहयि ।
- अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय, जहाँ कार्यावाही अंगरेजी या एक कषेत्रीय भाषा में की जाती है, हदी में अनुवाद उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के फैसले अक्सर नरिण्यों में उद्धृत होते हैं ।
 - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बहिर, हरयिणा और राजस्थान में नचिली अदालतें पहले से ही हदी का उपयोग करती हैं ।
- हदी भाषी राज्यों में केंद्र सरकार के अधकिरयिओं और अन्य करमचारयिओं द्वारा हदी के उपयोग को उनकी वार्षकि प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में दर्शाया जाएगा ।
- यह समति की जमिमेदारी और उत्तरदायतिव होगा कि आधकिरकि संचार में हदी भाषा को बढ़ावा दयि जाए ।
- आधकिरकि दस्तावेज़ और नर्मितरण पत्रों में भाषा को सरल बनाने के लयि विशिष्ट प्रस्ताव हैं ।
 - "आधकिरकि संचार में अंगरेजी भाषा के उपयोग को कम करने और हदी के उपयोग को बढ़ाने के लयि प्रयास कयि जाना चाहयि" ।
 - "कई सरकारी नौकरयिओं में हदी का ज्ञान अनविर्य होगा" ।

सफिरशैं राज्य सरकारों, उनके संस्थानों और वभिगों हेतु लक्षति:

- तमलिनाडु और केरल जैसे राज्यों को राजभाषा अधनियिम, 1963 एवं नयिमों और वनियिमों (अधनियिम के), 1976 के अनुसार छूट दी गई है ।
- कानून केवल 'A' श्रेणी के उन राज्यों में लागू कयि गया है, जनिमें आधकिरकि भाषा हदी है ।"
 - नयिमों के अनुसार, श्रेणी 'A' में बहिर, हरयिणा, हमिचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य एवं केंद्रशासति प्रदेश दल्लिी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं ।
 - श्रेणी 'B' में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्रशासति प्रदेश चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली शामिल हैं ।
 - अन्य राज्य, जहाँ हदी का उपयोग 65% से कम है, श्रेणी 'C' के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं ।
- समति ने सुझाव दयि है कि श्रेणी 'A' के राज्यों में हदी का शत-प्रतशित प्रयोग करने का प्रयास कयि जाना चाहयि ।
 - श्रेणी 'A' के राज्यों में IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों (KV) में शकिषा का माध्यम हदी होनी चाहयि, जबकि अन्य राज्यों में कषेत्रीय भाषा का इस्तेमाल कयि जाना चाहयि ।
- समति के अनुसार, सरकारी वभिगों में हदी का प्रयोग:
 - रक्षा और गृह मंत्रालयों में हदी का प्रयोग शत-प्रतशित है लेकिन शकिषा मंत्रालय अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँचा है ।
 - भाषा के उपयोग का आकलन करने के लयि समति के कुछ मानदंड थे ।
 - दल्लिी विश्वविद्यालय, जामयिा मलियिा इस्लामयिा, BHU और AMU सहति कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हदी का प्रयोग केवल 25-35% है, जबकि इसे शत-प्रतशित होना चाहयि था ।

राजभाषा पर संसदीय समिति:

- राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 351 द्वारा अनिवार्य रूप से हिंदी के सक्रिय प्रचार के साथ आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग की समीक्षा और प्रचार के लिये राजभाषा समिति का गठन किया गया था।
- समिति की पहली रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रस्तुत की गई थी।
- समिति का गठन और अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है और वर्ष 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 30 सदस्य (लोकसभा से 20 सांसद और राज्यसभा से 10 सांसद) हैं।
- अन्य संसदीय पैनल संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जबकि इसके विपरीत यह पैनल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो "रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा और सभी राज्य सरकारों को भेजेगा।

हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयास:

- **त्रिभाषा सूत्र (कोठारी आयोग 1968):**
 - पहली भाषा: यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
 - दूसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएँ या अंग्रेज़ी होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी।
 - तीसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेज़ी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेज़ी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी।
- वर्ष 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में भी "हिंदी, "संस्कृत" और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। NEP का मानना है कि कक्षा 5 से संभवतः कक्षा 8 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होगी।
 - NEP 2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये त्रिभाषा फॉर्मूले पर जोर देने का निर्णय लिया गया।

अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में भारत में हिंदी की स्थिति:

- वर्ष 2011 की भाषायी जनगणना के अनुसार: भारत में 121 मातृभाषाएँ हैं।
 - 8 करोड़ व्यक्ति या यूनं कर्हे का 43.6% आबादी ने हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित किया और 11% आबादी ने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में बताया है।
 - अतः 55% आबादी हिंदी को या तो मातृभाषा के रूप में या अपनी दूसरी भाषा के रूप में जानती है।
 - 72 करोड़ उपयोगकर्ताओं और 8% जनसंख्या के साथ, बांग्ला भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
 - बांग्ला, मलयालम और उर्दू भाषाओं में गरिवट आई है लेकिन हिंदी और पंजाबी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है।
 - वर्ष 1971 से वर्ष 2011 के बीच हिंदी बोलने वालों की संख्या 2.6 गुना बढ़कर 20.2 करोड़ से 52.8 करोड़ हो गई।

हिंदी की संवैधानिक स्थिति:

- भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- अनुच्छेद 351: यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मशरूति संस्कृति में सभी के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
- अनुच्छेद 348 (2) यह भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348 (1) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार, देवनागरी लिपि में हिंदी, संघ की आधिकारिक भाषा होगी।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 धारा 7 के तहत प्रावधान करता है कि अंग्रेज़ी भाषा के अलावा किसी राज्य में हिंदी या राजभाषा का उपयोग, भारत के राष्ट्रपति की सहमति से राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय, आज्ञा आदि प्रयोजन के लिये अधिकृत किया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यूनसिफ द्वारा 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है।
2. बांग्ला को राष्ट्रीय भाषाओं में से एक बनाने की मांग पाकिस्तान की संविधान सभा में उठाई गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- पाकस्तान की संविधान सभा ने 23 फरवरी, 1948 को कराची में अपने सत्र में प्रस्ताव दिया कि सदस्यों को विधानसभा में उर्दू या अंग्रेजी में बोलना होगा। पूर्वी पाकस्तान कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य धीरेन्द्रनाथ दत्ता ने बांग्ला को संविधान सभा की एक भाषा के रूप में शामिल करने के लिये संशोधन प्रस्ताव पेश किया। उसी वर्ष, पाकस्तान के डोमिनियन की सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया, जिसका पूर्वी बांग्ला के बांग्ला भाषी बहुमत वाले क्षेत्र में व्यापक विरोध हुआ।
- ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने कानून की अवहेलना की और 21 फरवरी, 1952 को एक विरोध प्रदर्शन किया। वर्षों के संघर्ष के बाद सरकार ने नरमी बरतते हुए वर्ष 1956 में बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया। बांग्लादेश में, 21 फरवरी को भाषा आंदोलन दिस मनाया जाता है। **अतः कथन 2 सही है।**
- प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिस मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था, न कि यूनिसैफ द्वारा। यह भाषा आंदोलन और दुनिया भर के लोगों के जातीय अधिकारों के लिये सम्मान प्रदर्शन है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

अतः विकल्प B सही उत्तर है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/fresh-hindi-imposition-row)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/fresh-hindi-imposition-row>

